www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 176 | जौनपुर मंगलवार, 10 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पहले हाईकोर्ट जाएं, गुंडा राज अस्वीकार्य : सीजेआई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की एक जिला अदालत में वकील और उसके मुवक्किल पर हुए हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। यहां वकील ने घटना का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली की तीस हजारी जिला अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) हरदीप सिंह पाल की अदालत के अंदर उन पर और उनके मुवक्किल पर हमला हुआ। वकील के मुताबिक, जब वह अपने मुवक्किल (जो एक आरोपी है) की पैरवी कर रहे थे, तभी शिकायतकर्ता और कुछ गुंडों ने उन दोनों को बुरी तरह पीटा।वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि हमलावरों ने कोर्ट रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उस समय जज और कोर्ट के कर्मचारी भी वहीं मौजूद थे। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी का पक्ष लेने की वजह से उन्हें भी निशाना बनाया गया।इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने वकील से सवाल किया कि क्या उन्होंने इस घटना की जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दी है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले में दखल नहीं दे रही है, तो यह कानून की अवहेलना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गुंडा राज बताया और कहा कि ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

आरबीआई की एसओपी पूरे भारत में लागू करे सरकार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए इसे डकैती या लूट करार दिया है। अदालत ने कहा कि अब तक ध्54,000 करोड़ से अधिक की राशि साइबर ठगी के जरिए निकाली जा चुकी है, जो बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को पूरे देश में औपचारिक रूप से लागू किया जाए, ताकि डिजिटल फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की लापरवाही या अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और बैंकों से कहा कि वे ऐसे मामलों में समय पर और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। सुनवाई के दौरान अदालत ने बताया कि आरबीआई ने पहले ही एक एसओपी तैयार किया है, जिसके तहत साइबर फ्रॉड की आशंका होने पर अस्थायी रूप से डेबिट कार्ड को होल्ड पर डालने जैसी त्वरित कार्रवाई का प्रावधान है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को तुरंत रोकना है।डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम निर्देश दिया है।

छात्रों में सपनों को सच करने की क्षमता : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण का दूसरा एपिसोड सोमवार को जारी किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे विद्यार्थियों में अपने सपनों को सच करने की पूरी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे विद्यार्थियों में अपने सपनों को सच करने की पूरी क्षमता है। परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि कैसे वे अपनी प्रतिभा और कौशल का सार्थक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने संस्कृत सुभाषित भी शेयर किया। उन्होंने प्राचीन संस्कृत श्लोक का हवाला देते हुए लिखा, विद्या वितर्को विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता

क्रिया। यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमतिवर्तते इसका अर्थ है, श्विद्या, तर्कशक्ति, विज्ञान, स्मृति–शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, ये छह जिसके पास हैं, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में पीएम मोदी की छात्रों के साथ बातचीत को दिखाया जाएगा। इस एपिसोड में पीएम मोदी एग्जाम की तैयारी करते समय कॉन्फिडेंट रहने, रूटीन फॉलो करने और खुद पर भरोसा रखने के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करेंगे। परीक्षा पे चर्चा 2026 का पहला एपिसोड 6 फरवरी को जारी किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एपिसोड में कहा कि बहुत सारे छात्रों ने यह सुझाव दिया था कि देश के अलग–अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2018 के बाद प्रधानमंत्री मोदी हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) करते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव को कम करना और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित करता है। साल 2025 के कार्यक्रम में 5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। 2026 के संस्करण में 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए। अतिरिक्त 2.26 करोड़ प्रतिभागी संबंधित गतिविधियों में शामिल हुए, जिससे कुल मिलाकर 6.76 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी देखने को मिलेगी।

विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र का आज नौवां दिन है। लोकसभा से आठ सांसदों के निलंबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य को कथित तौर पर रोके जाने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्षी दलों के बीच गतिरोध बरकरार है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में काम जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है, तो बजट सत्र के आने वाले दिन भी हंगामे भरे रह सकते हैं। विपक्ष राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें। विपक्ष के नेता इसके बाद भी नहीं माने और हंगामा जारी रखा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने संसद को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को 8वें दिन भारी हंगामे के चलते सभा तीन बार स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी सोमवार को हंगामे के आसार हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर तीखी बहस हुई थी।बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कह दिया था, जिसके बाद विवाद हो गया था।विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू होने के पांच मिनट बाद ही दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में हंगामे पर प्रियंका गांधी का सवाल– विपक्ष का गला घोंटा जा रहा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न दिए जाने के बाद लोकसभा में मचे हंगामे के बीच, पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि यह लोकतंत्र नहीं है जहां विपक्ष के नेता को अपने विचार रखने की अनुमति न दी जाए। मीडिया से बात करते हुए प्रियंका ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी को एक मिनट भी बोलने की अनुमति न देना हास्यास्पद है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि हम सदन (लोकसभा) जाते हैं और बस बाहर आ जाते हैं। विपक्ष के नेता को एक मिनट भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। यह हास्यास्पद है। यह लोकतंत्र नहीं है। हम यहां किसलिए आते हैं? उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह घटना तब हुई जब विपक्ष द्वारा राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न दिए जाने के विरोध में कई बार सदन स्थगित करने के बाद सदन फिर से शुरू हुआ। विपक्ष के विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें अपने विचार रखने की अनुमति दी जाएगी। गांधी ने सदन में कहा कि एक घंटे पहले सदन का एक सदस्य अध्यक्ष के पास गया था, अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया था कि मुझे यहां बोलने और बजट चर्चा से पहले कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे वे मुद्दे उठाने की अनुमति है या नहीं? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में लगातार व्यवधान पैदा करने के लिए विपक्ष की आलोचना की।

सीएम योगी ने बजट सत्र के दौरान चलने वाले स्वास्थ्य शिविर का किया उद्घाटन

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान भवन में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए लगाया गया है। इसमें केजीएमयू के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। शिविर के उद्घाटन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा यह शिविर लगाया गया है। यह शिविर माननीय सदस्यों व

अन्य लोगों की सुविधा के लिए भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ दिनचर्या हर नागरिक का अधिकार होनी चाहिए। सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस पर काम कर रही है। सीएम ने सदस्यों को तमाम उतार–चढ़ाव के बावजूद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर सदस्य को तनावमुक्त रहकर उन्मुक्त वातावरण में दिनचर्या रखनी चाहिए, इससे रोग आकर भी भाग जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हर व्यक्ति की बात महत्वपूर्ण होती है। नेता विकास, डॉक्टर स्वास्थ्य और जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, उस विषय की बातें करेगा तो इसका प्रभाव आमजन पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की। उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी का आभार प्रकट किया। स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, बलदेव सिंह औलख, केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद, एसजीपीजीआई के निदेशक आरके धीमन आदि मौजूद रहे।

एनसपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ी

मुंबई, (एजेंसी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, 85 वर्ष, को सोमवार दोपहर गले में खराश और खांसी की शिकायत के बाद बारामती स्थित उनके आवास से पुणे के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था। एनसीपी (एसपी) प्रमुख के भतीजे श्रीनिवास पवार ने बताया कि पवार को कल रात से लगातार खांसी आ रही थी और सीने में जकड़न के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पुणे ले जाया गया। रूबी हॉल क्लिनिक के मुख्य हृदय रोग विशेषज्ञ और प्रबंध न्यासी डॉ. परवेज ग्रांट ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। डॉ. ग्रांट ने कहा कि पहुँचने पर डॉक्टरों की एक टीम उनकी जाँच करेगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

शरद पवार मुख कैंसर से उबर चुके हैं, जिसका निदान 1990 के दशक के उत्तरार्ध में हुआ था। उन्होंने इस बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका और भारत में कई सर्जरी करवाईं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता रोहित पवार ने शनिवार को कहा कि हवाई दुर्घटना में अजित पवार की मौत की परिस्थितियों के बारे में सभी को संदेह है और वह 10 फरवरी को इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति देंगे। बारामती में जिला परिषद चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि अजित पवार चाहते थे कि राकांपा के दोनों गुट एकजुट हो जाएं और विलय की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव शनिवार को हुए। यह मतदान मूल रूप से पांच फरवरी को होना था, लेकिन 28 जनवरी को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु और इसके बाद तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दिवंगत राकांपा प्रमुख के भतीजे रोहित पवार ने कहा कि हर किसी के मन में (दुर्घटना के बारे में) सवाल और संदेह हैं। मैं 10 फरवरी को मुंबई में एक प्रस्तुति दूंगा। दुर्घटना क्यों हुई और यह कैसे हुई होगी, ये मुद्दे 10 फरवरी को उठाए जाएंगे। जिला परिषद चुनाव के लिए राकांपा (शप) और राकांपा ने हाथ मिलाया है और दोनों 'घड़ी' चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार राकांपा के प्रमुख थे, जबकि उनके चाचा शरद पवार राकांपा (शप) के प्रमुख हैं।

रूसी तेल की खरीद को लेकर मंत्रियों के बयानों पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते और रूस से तेल खरीद रोकने पर केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल के बयान सामने आए हैं, जिन पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सरकार के नजरिए में ही खामियां हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जिसे पूरी सरकार का दृष्टिकोण बताते हैं, उसके बारे में बड़ी–बड़ी बातें करते हैं, उसमें ही खामियां हैं। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा एक पोस्ट में जयशंकर, पीयूष गोयल और हरदीप पुरी पर निशाना साधते हुए लिखा, श्रूसी तेल मुद्दे और भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री से पूछो, और पेट्रोलियम मंत्री दूसरे मुद्दों में व्यस्त हैं। ये भारत–अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार के नजरिए में ही खामी है। शनिवार को भारत–अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे में, भारत ने अगले पांच वर्षों में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातु, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोयला खरीदने का इरादा व्यक्त किया है। समझौते के तहत अमेरिका, भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर लगे अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को भी हटा दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद कर दी है। एक इंटरव्यू के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से जब रूस से तेल खरीद बंद करने को लेकर सवाल किया गया ।

संजय राउत का सलमान खान और आरएसएस पर बड़ा हमला

मुंबई, (एजेंसी)। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े कार्यक्रम में सलमान खान समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुईं। संजय राउत ने इस पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या सलमान खान को सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया था? उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया कि क्या यह कदम सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि अब संघ में मुसलमानों का स्वागत है? राउत ने यह भी दावा किया कि कई लोग वहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव में गए थे। संजय राउत ने अपनी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से एक खास अपील की है। उन्होंने कहा कि उद्धव जी को फिर से विधान परिषद में लौटना चाहिए। राउत के अनुसार, मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके उद्धव ठाकरे की मौजूदगी राज्य के लोगों और विपक्ष की मजबूती के लिए विधानसभा में बहुत जरूरी है। यह पूरे महा विकास अघाड़ी गठबंधन की इच्छा है। मुंबई की नई मेयर रितु तावड़े को लेकर भी संजय राउत ने कड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने उन्हें श्कांग्रेस से उधार लिया हुआश उम्मीदवार बताया। राउत ने दावा किया कि बीजेपी को केवल शिवसेना (यूबीटी) के दबाव की वजह से एक मराठी मेयर नियुक्त करना पड़ा है ।

लोकसभा में भारी हंगामा, कार्यवाही स्थगित, राहुल गांधी ने स्पीकर पर लगाया ये आरोप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सोमवार को सुबह 11 बजे सत्र शुरू होने के बाद दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे सत्र पुनः शुरू हुआ और लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर चर्चा की मांग जारी रखी और संसद के निचले सदन को 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया गया था कि बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें कुछ मुद्दे उठाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने वादे से मुकर रहे हैं। राहुल गांधी ने कार्यवाही की अध्यक्षता

कर रही सांसद संध्या राय से कहा कि अध्यक्ष ने हमें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि मुझे बजट पर चर्चा से पहले बोलने की अनुमति दी जाएगी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल के बीच हुई बैठक में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, जिसमें वे भी उपस्थित थे। रिजिजू ने सदन को बताया कि अध्यक्ष महोदय ने सदन में यह बात कही थी, वेणुगोपाल जी वहां मौजूद थे, मैं भी शामिल हुआ था। अध्यक्ष ने कहा था कि अगर सभी सहमत हैं तो सदन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। वेणुगोपाल ने भी कहा था कि वे अपने विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहते हैं, हमने उनसे पूछा कि आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं। अगर वे अध्यक्ष पर किसी बात का आरोप लगाते हैं तो अध्यक्ष भी उसका जवाब देंगे। राहुल गांधी ने जो कहा है वह 100 प्रतिशत झूठ है, अध्यक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सभा की अध्यक्ष संध्या राय ने कहा कि उन्हें निचले सदन में विपक्ष के नेता द्वारा कोई मुद्दा। उठाने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

संपादकीय

अमल की ताक में अदालत के महत्त्वपूर्ण आदेश

आरटीई कानून लागू हुए 16 वर्ष गुजर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से जाहिर है कि सरकारों ने उस धारा के तहत अपने दायित्व को नहीं निभाया। यानी लड़कियों के लिए अलग शौचालय की जरूरत पूरी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या का ऊंचा सैद्धांतिक महत्त्व है कि मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संविधान प्रदत्त जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को इससे संबंधित सुविधाएं मिलें, यह सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। इस सिलसिले में लड़के, लड़कियों, और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग शौचालय बनाने तथा लड़कियों को सेनेटरी पैड मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट की ये राय सटीक है कि मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य के सुरक्षित, प्रभावी, और किफायती उपाय उपलब्ध ना होने पर लड़कियों की गरिमा प्रभावित होती है। इसलिए अदालत ने इन सुविधाओं को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिकाओं का मौलिक अधिकार बना दिया है। यानी न्यायालय ने जीवन के अधिकार संबंधी अनुच्छेद का विस्तार किया है। ठीक ऐसा ही विस्तार एक दशक पहले कोर्ट की एक संविधान पीठ ने किया था, जब निजता को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। दरअसल, गुजरे दशकों में कोर्ट ने अपने कई महत्त्वपूर्ण निर्णयों एवं व्याख्याओं के जरिए नागरिक समाज के विभिन्न समूहों के मौलिक अधिकारों का विस्तार किया है। लेकिन बात घूम–फिर कर अमल पर आ जाती है। पूर्व निर्णय से निजता कितनी सुरक्षित हुई? खुद संसद ने जीवन के बुनियादी हक संबंधी अनुच्छेद 21 में उपधारा 21–ए जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को बच्चों का मूल अधिकार बनाया था। उसके तहत स्कूल को खास ढंग से परिभाषित किया गया, जिसमें लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की अनिवार्यता उपलब्धता शामिल है। यह कानून लागू हुए 16 वर्ष गुजर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से जाहिर है कि सरकारों ने उस धारा के तहत अपने दायित्व को नहीं निभाया। यानी ये जरूरत पूरी नहीं की गई। तो नए आदेश पर पालन सुनिश्चित कौन कराएगा? इसका उल्लंघन होने पर जवाबदेही कैसे तय होगी? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनेक संवैधानिक प्रावधान, कानून, और सर्वोच्च अदालत के महत्त्वपूर्ण आदेश आज भी अमल की ताक में हैं। अतरू सुप्रीम कोर्ट को इस समस्या का भी निवारण करना चाहिए। वरना, उसका ताजा निर्णायक भी महज सैद्धांतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बना रह जाएगा।

विकसित भारत 2047 की ओर स्मार्ट रास्ता – हड़ताल नहीं, बल्कि श्रम संहिता

डॉ. दीपक जायसवाल

पीढ़ियों से, भारत के श्रमिकों ने एक पुरानी और टुकड़ों में बंटी श्रम प्रणाली का बोझ उठाया है, जो अक्सर उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। असंगठित, संविदा और उभरते गिग क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक नीति–परिदृश्य में अदृश्य रहे हैं और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं। चार श्रम संहिताएँ इन ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग तीन दर्जन अलग–अलग कानूनों को एक सुसंगत, एकल ढांचे में लाकर, ये संहिताएँ न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, जो लंबे समय से वंचित रहे हैं। वर्षों के परामर्श और बहस के बाद इनका कार्यान्वयन, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने तथा अधिक स्थिर और मानवतापूर्ण रोजगार वातावरण बनाने में निर्णायक क्षण का प्रतीक है। एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में, भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू), कामगारों की दीर्घकालिक भलाई, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोर्चा दृढ़ता से मानता है कि 12 फरवरी को श्रम संहिताओं के खिलाफ हड़ताल में भाग लेना न तो आवश्यक है और न ही वर्तमान समय में श्रमिक वर्ग के सर्वोत्तम हित में है। श्रम संहिताएं कोई अचानक या एकतरफा हस्तक्षेप नहीं हैं। ये दो दशकों से अधिक समय तक चली सुधार प्रक्रिया का परिणाम हैं। 29 अलग–अलग श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अस्पष्टता को कम किया जा सके तथा कार्य और रोजगार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप भारत की श्रम रूपरेखा को आधुनिक बनाया जा सके। श्रम संहिताओं को पूरी तरह खारिज करना उन मौलिक लाभों की उपेक्षा करता है, जो वे श्रमिकों को प्रदान करने का प्रयास करती हैं। वेतन संहिता सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद वेतन सुरक्षा के अंतर को दूर किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, पहली बार, असंगठित, संविदा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विधायी रूपरेखा तैयार करती है। इन श्रमिकों की संख्या लगभग 40 करोड़ है और पहले ये श्रमिक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। ये प्रावधान भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का ऐतिहासिक विस्तार प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता तथा पेशे से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य–परिस्थिति संहिता का उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, तेज विवाद निवारण और सुरक्षित, स्वस्थ व अधिक सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है। कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं, अनुभव बताते हैं कि व्यापक विरोध और हड़तालों से शायद ही रचनात्मक परिणाम मिलते हैं। संवाद, नियम–आधारित सुधार और मुद्दा–विशेष पर चर्चा के जरिये श्रमिकों के हित बेहतर तरीके से पूरे किये जा सकते हैं, बजाय इसके कि आपस में टकराव हो, जिससे पारिश्रमिक हानि, उत्पादन में रुकावट और रोजगार असुरक्षा का जोखिम पैदा होता हैकृविशेष रूप से श्रम बल के सबसे कमजोर वर्गों के लिए। यह दावा करना भी गलत है कि श्रम संहिताएँ बिना परामर्श के लागू की गई हैं। सुधार प्रक्रिया में त्रिपक्षीय चर्चाओं के कई दौर, संसद की स्थायी समितियों में विचार–विमर्श और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद शामिल थे। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बातचीत और संस्थागत संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि उन व्यवधानों के द्वारा जो अंततरू स्वयं श्रमिकों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूपांतरण के दौर से गुजर रही है और राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, श्रमिक संघों को विघटन के बजाय जिम्मेदार कार्रवाई का चयन करना चाहिए। हमारी भूमिका केवल सुधारों का विरोध करना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह आकार देना है कि श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा को प्रभावी क्रियान्वयन और सतत सुधार के माध्यम से व्यावहारिक तौर पर मजबूत किया जा सके। श्रमिक संघों की वास्तविक जिम्मेदारी केवल विरोध ा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों को वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर लाभ हो। अब ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि श्रम संहिताओं को न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए और इन्हें हर उस मजदूर तक पहुँचाया जाए, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। हड़ताल की बजाय संवाद, सहयोग और निरंतर सुधार चुनकर, श्रमिक संघ एक ऐसा प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं, जो श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा प्रदान करती हो और साथ ही 2047 तक विकसित भारत की ओर देश की यात्रा का भी समर्थन करती हो।

भारत पर नजर रखो, दिन ला दिए मोदी जी

शकील

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यह तो बता रहे हैं कि कौन कौन से उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। मगर यह नहीं बता रहे कि कौन कौन से आएंगे। सारा खेल इसी में छुपा है। अमेरिका जो चाहेगा वह आएगा। जीएम (जेनेटिक मोटिफाइड) फसलों के लिए वह भारत को प्रयोगशाला बनाएगा। यही कहा जा रहा है कि मीडिल क्लास चेत जाए। यह जीएम फसलें इस पीढ़ी को नहीं अगली कई पीढ़ियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगी यह सोचना भी बहुत डरावना है। डीएनए बदल जाएगा।किसी से लड़ना, अवाइड करना या और कुछ भी तिरस्कार वगैरह इन सबसे बुरी बात समझी जाती है नजर रखना। नजर किस पर रखी जाती है? वह तो सब ठीक है अपराधी वगैरह। लेकिन उससे भी बुरी बात है नजर अपने आश्रित पर रखी जाती है। शब्द बहुत गंदा है मगर सच वही है कि गुलाम पर। कि वह गुलामी से बाहर जाने की तो नहीं सोच रहा। नजर रखो इस पर। तो मोदी जी आज भारत को इस स्थिति पर ले आए कि अमेरिका के अधिकारी हम पर निगाह रखेंगे। अब क्या कहें? हद तो यह हो गई कि इस शर्मनाक स्थिति में लाने को मोदी अपनी शान समझ रहे हैं! संसद परिसर में एनडीए के सांसदों से अपना स्वागत करवा रहे हैं। हार पहन रहे हैं। जीत का!हम किस से तेल खरीदेंगे किस से नहीं यह अमेरिका तय करेगा। और हम उसके अनुसार करेंगे। मगर फिर भी वह हम पर निगाह रखेगा। इससे ज्यादा शर्म की, अपमान की बात और क्या हो सकती है। लेकिन क्या यह भारत का अपमान है? ऊपर से देखने में हैं। मगर वास्तव में यह मोदी का पराभव है। सारी नकली कलई खुल गई। 56 इंच की छाती, लाल आंखों और एक अकेला सब पर भारी की असलियत सब के सामने आ गई। अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल गांधी के शब्दों में नरेन्द्रबाहर इस तरह सरेन्डर किया और यहां राहुल का सामना होने से डर कर लोकसभा में नहीं आए। राहुल ने सुबह कहा था मोदी जी में लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं है। उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना था। मगर वे वास्तव में नहीं आए और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष से कहलवाया यह गया कि मोदी को सदन में खतरा था। विपक्ष की महिला सांसदों से। इसलिए नहीं आए।प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा! वह भी महिला सांसदों से! बहुत बड़ा मजाक हो गया यह। और यहीं से मोदी जी की उलटी गिनती की शुरुआत हो जाती है। विदेशों से भारत की निगरानी का फरमान आता है और उन्हें जवाब देना तो दूर वे देश में अपनी लोकसभा में जिसके वे नेता हैं वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें वहां खतरा दिखता है।अमेरिका से डील मोदी की है। कमजोर और लाचार भारत दिख रहा है। भारत न कभी था न कभी है। लेकिन जैसा कि भक्तों ने मोदी का मतलब भारत कर दिया था। वैसा ही अब मोदी के कमजोर होने से अमेरिका भारत को कमजोर समझ रहा है। उस पर नजर रखने की बात कर रहा है। इसका जवाब विपक्ष तो कड़े शब्दों में दे ही रहा है। कांग्रेस ने साफ कह दिया कि आपकी जो भी सीक्रेट अमेरिका के पास हों हमें कोई मतलब नहीं है। आप इस वजह से सरेंडर कर दीजिए मगर भारत नहीं झुकेगा। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चौयरमेन पवन खेड़ा ने यह कहते हुए एपस्टीन फाइल का भी ि◌ाक्र किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी कर चुके हैं। एपस्टीन फाइल में नाम आया है। संदेश यही जा रहा है कि एपस्टीन फाइल की वजह से ट्रंप मनमानी कर रहा है। पहले उसने सीज फायर करवाया। और फिर यह डील। जो पूरी तरह इकतरफा है। भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ। भारत का जो सामान पहले अमेरिका 3 परसेन्ट टैरिफ देकर जाता था। अब 18 परसेन्ट देकर जाएगा। सामान्य शब्दों में पहले भारत के बने सामान पर अमेरिका केवल तीन प्रतिशत शुल्क (टैरिफ) लेता था। फिर उसने हमें धमकाते हुए पहले 50 प्रतिशत किया। सौ प्रतिशत की धमकी दी। फिर 25 प्रतिशत पर लाया। और अब जो नई डील हो गई है उस में 18 प्रतिशत लेगा। मतलब तीन से 18 प्रतिशत बढ़ाया गया है और हमारे प्रधानमंत्री इस अपनी जीत बताते हुए विजय माला पहन रहे हैं। और देखिए! डील में इससे भी ज्यादा जो खतरनाक पहलू है जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है वह है अमेरिका के लिए अपना पूरा बाजार खोल देना। अमेरिका कह रहा है कि इस डील से उसका किसान मालामाल हो जाएगा। और हमारे किसान का दिवाला निकल जाएगा। अमेरिका से जो कृषि और डेयरी उत्पाद आएंगे वह टैरिफ फ्री होंगे। मतलब उस पर भारत एक पैसा भी शुल्क (टैरिफ) नहीं लगाएगा। अमेरिका को जो भी अतिरिक्त उत्पादन है वह सब यहां डंप किया जाएगा। भारत का किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। किसान संगठनों ने कहा है कि यह तीन काले कानूनों से बड़ी तबाही होने जा रही है। उसके साफ शब्द हैं कि उन्हें सरकार की सफाइयों पर भरोसा नहीं है। डील में जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। अमेरिका का साफ कहना है वह इसके जरिए 500 अरब डालर का माल भारत में बेचेगा। 500 अरब डालर मतलब 45 लाख करोड़ रुपए! यह भी समझना मुश्किल है इतना रुपया कितना होता है? तो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि अभी जितना माल विदेशों से भारत आता है उसका ढाई गुने से ज्यादा केवल अमेरिका से हमें आयात करना होगा। और माल आता हो तो किसका पैसा जाता है। आम भारतीय का ही। उससे यही माल खरीदवाया जाएगा। किसकी कीमत पर? भारतीय किसान और पशुपालक की कीमत पर। प्रचार और कीमतों में काम्पीटिशन करवा कर वे भारतीय किसान को मुकाबले से बाहर कर देंगे।खतरे बहुत बड़े हैं। जनता को ही समझना होंगे। और अगर नहीं समझती तो वह आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी की कहानी लिखने में खुद भी शामिल मानी जाएगी। कांग्रेस ने मध्यम वर्ग को सचेत किया है। माहौल वही बनाता है। मोदी मोदी का जाप सबसे पहले उसी ने किया था। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यह तो बता रहे हैं कि कौन कौन से उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। मगर यह नहीं बता रहे कि कौन कौन से आएंगे। सारा खेल इसी में छुपा है। अमेरिका जो चाहेगा वह आएगा। जीएम (जेनेटिक मोटिफाइड) फसलों के लिए वह भारत को प्रयोगशाला बनाएगा। यही कहा जा रहा है कि मीडिल क्लास चेत जाए। यह जीएम फसलें इस पीढ़ी को नहीं अगली कई पीढ़ियों को क्या नुकसान पहुंचाएंगी यह सोचना भी बहुत डरावना है। डीएनए बदल जाएगा। यह संयोग प्रयोग डीएनए ऐसे शब्दों का प्रधानमंत्री बहुत उपयोग करते हैं। मगर क्या इनका मतलब उन्हें मालूम है? भारत में जीएम फसलों पर रोक है। केवल कपास की खेती की अनुमति है। यह बहुत बड़ी बहस है कि खाने–पीने की चीजें जीएम होना चाहिए या नहीं और इसका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रयोग भारतीय लोगों पर किया जाएगा? बहुत संक्षेप में जीएम मतलब किसी बीज, जीव या पौधे के जीन को दूसरे में आरोपित कर एक नई प्रजाति विकसित करना।

जापान में सना ए. ताका इची को प्रचंड जनादेश और विपक्ष का सूपड़ा साफ कर जनता ने संदेश दिया

नीरज

जापान में निचले सदन के चुनाव परिणाम ने देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री सना ए. ताका इची के नेतृत्व वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। पहले चरण के मतगणना के परिणामों के अनुसार ताका इची की पार्टी अकेले ही निचले सदन में 316 सीटें जीतने में सफल रही तथा उसने गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर कुल 352 से अधिक सीटों का दो–तिहाई बहुमत हासिल कर लिया। इस प्रकार वह अकेले ही अपनी पार्टी के बहुमत से कहीं आगे निकल गईं और विपक्ष को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया क्योंकि प्रधानमंत्री ताका इची ने महज कुछ ही महीनों पहले सत्ता संभाली थी और यह उनका पहला आम चुनाव था। उन्होंने तीन महीने पहले ही निचले सदन को भंग कर दिया था ताकि जनता से स्पष्ट जनादेश लिया जा सके। चुनाव के दिन भी देश के कई हिस्सों में जोरदार बर्फबारी और ठंडे मौसम के कारण मतदान केन्द्रों पर कठिन परिस्थितियाँ पैदा हुईं, लेकिन इसके बावजूद मतदाताओं की भागीदारी अपेक्षाकृत मजबूत रही। यह दर्शाता है कि जापानी जनता ने ठंडे मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले में भाग लेने की प्रतिबद्धता दिखाई। इस चुनाव में विपक्षी दलों को जिस प्रकार की पराजय मिली, वह जापानी राजनीति के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम था। मुख्य विपक्षी गठबंधन और छोटे दलों ने जिस तरह अपनी सीटें गंवाईं, उससे स्पष्ट होता है कि इस समय जनता ने ताका इची के नेतृत्व को अधिक भरोसेमंद और स्थिर विकल्प के रूप में चुना। अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि मतदान के पीछे मुख्य कारण आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के साथ सुरक्षा नीतियों पर मतदाताओं की चिंताएँ थीं, जिनके प्रति उन्होंने ताका इची की स्पष्ट सोच को प्राथमिकता दी। ताका इची की जीत का विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि यह सिर्फ संख्या की जीत नहीं है, बल्कि यह एक राजनैतिक विश्वास का जनादेश भी है। जापान पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते आर्थिक दबाव, बुजुर्ग आबादी से जुड़ी सामाजिक चुनौतियों और बढ़ते क्षेत्रीय तनावों के बीच अपना रास्ता ढूंढ़ रहा है। चीन के साथ संबंधों में तनाव, ताइवान को लेकर बदलती भू–राजनीति तथा अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी जैसी विषयों को लेकर जनता के भीतर मजबूत भावनाएँ हैं। ताका इची ने चुनाव के दौरान स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया था कि जापान को न केवल आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है बल्कि उसे अपनी रक्षा और वैश्विक भूमिका को भी मजबूती से परिभाषित करना होगा। हम आपको बता दें कि सना ताका इची स्वयं एक लंबा राजनीतिक अनुभव लिये हुए हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1990 के दशक में संसद सदस्य के रूप में शुरू की थी और समय–समय पर कई महत्वपूर्ण विभागों तथा मंत्रालयों में काम किया। अपने अनुभव, दृढ़ नीतियों और स्पष्ट विचारधारा के कारण उन्हें पार्टी में एक मजबूत छवि मिली। वह इस चुनाव से पहले जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं और इस जीत ने उन्हें अपनी पार्टी तथा जनता दोनों से मजबूत समर्थन दिलाया है। ताका इची ने अपने राजनीतिक कॅरियर में व्यापक विषयों पर सार्वजनिक रूप से अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिनमें आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जापान की अंतरराष्ट्रीय भूमिका शामिल हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी की जीत का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने आर्थिक स्थिरता, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को चुनाव में प्रमुख मुद्दों के रूप में उठाया। जापान की अर्थव्यवस्था बड़े कर्ज, कम उत्पादन वृद्धि और बढ़ते जीवनयापन लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रही थी, जिनके समाधान के लिये जनता अधिक ठोस नीतियों की उम्मीद कर रही थी। ताका इची ने यह विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिये गंभीर प्रयास करेगी और एक दीर्घकालिक आर्थिक सुधार योजना लागू करेगी। सुरक्षा मामलों में उनकी विचारधारा और भी अधिक स्पष्ट रही है। उन्होंने बार–बार यह कहा कि जापान को अपनी रक्षा नीतियों को अधिक आत्मविश्वास तथा स्वतंत्रता के साथ परिभाषित करना चाहिए। अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारियों को और मजबूती प्रदान करना, क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना तथा चीन और उत्तर कोरिया जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना उनकी प्राथमिकता रही है। इस दृष्टिकोण ने उन मतदाताओं को प्रभावित किया जो जापान की क्षेत्रीय स्थिति को एक जटिल तथा बढ़ती चुनौतियों वाला क्षेत्र मानते हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस चुनाव के परिणाम का प्रभाव देखा जा रहा है। इंडो–पैसेफिक क्षेत्र में जापान की भूमिका महत्वपूर्ण है और ताका इची की जीत ने यह संकेत दिया है कि जापान वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तथा आर्थिक साझेदारियों में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिये तैयार है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, मुक्त व्यापार और सहयोग के लिये एक सकारात्मक संकेत है। जापान की बढ़ती भूमिका ने अमेरिका तथा अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर कई साझेदारी योजनाओं को गति दी है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि ताका इची सरकार इस दिशा को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। साथ ही भारत–जापान के बीच लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। इसी कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताका इची को उनकी शानदार जीत पर व्यक्तिगत रूप से बधाई दी है। मोदी ने यह स्पष्ट किया कि भारत और जापान दोनों ही लोकतंत्रों के साझा मूल्यों, क्षेत्रीय स्थिरता तथा आर्थिक सहयोग के लिये दृढ़ संकल्पित हैं। मोदी की बधाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत जापान के साथ साझेदारी को और गहरा करना चाहता है, विशेष रूप से रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा क्षेत्रीय सामरिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में। यह बधाई न केवल व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इसका व्यापक महत्व यह है कि भारत दोनों देशों के बीच एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण को और अधिक मजबूत करना चाहता है। भारतीय–जापानी सहयोग का दायरा हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है और इस चुनाव के परिणाम ने इसे और प्रोत्साहन दिया है। बहरहाल, 2026 का यह जापान चुनाव परिणाम दिखाता है कि जनता ने ठोस नेतृत्व, स्पष्ट नीतियों तथा देश की रणनीतिक दिशा को समर्थन दिया है। सना इची की जीत सिर्फ एक संसदीय बहुमत नहीं है, बल्कि यह जापान के भविष्य की दिशा को लेकर एक व्यापक विश्वास का प्रतीक भी है। यह जीत जापान को आर्थिक, सामाजिक और सामरिक रूप से एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिये तैयार कर देती है और अब वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण बनने वाली है।

मतदाताओं को सीधे कैश ट्रांसफर मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

डॉ. ज्ञान

कोर्ट ने चुनावी हार, सीटों के नुकसान, या प्रचार पाने का जिक्र करते हुए राजनीतिक टिप्पणी को कानूनी क्षेत्राधिकार के साथ मिलाकर गलती की है। अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक लोकप्रियता को संवैधानिक न्याय से अलग रखें। श्व्यवस्थित प्रभाव डालनेश की जांच किए बिना याचिका पर सुनवाई से इंकार करना भी गलत है सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव के दौरान चुनावी आदर्श आचार संहिता (एससीसी) लागू होने के बाद मतदाताओं को सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा सीधे कैश ट्रांसफर, भारतीय चुनाव आयोग का इस तरह से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर आंखें मूंद लेना, और मतदान के दिन लाभार्थियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार करना अनुचित है क्योंकि इसमें पहचानने योग्य कानूनी कमजोरियां हैं और साथ ही राजनीतिक रंग भी, जिसने एक याचिकाकर्ता राजनीतिक पार्टी को चुनाव में उसकी विफलता के लिए उपहासपूर्ण टिप्पणी की, जबकि आरोप के गुण–दोष में जाए बिना इसे न सुनने के लिए एक आधार बनाया भी बनाया।शुक्रवार (6 फरवरी) को जाने–माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी (जेएसपी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने और सत्तारूढ़ प्रतिष्ठानों द्वारा चुनाव जीतने के लिए अपनाई गई भ्रष्ट प्रथा को रोककर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशानिर्देश बनाने और समुचित निर्देश देने की मांग की थी।सबसे परेशान करने वाली बात मुख्य न्यायाधीश की राजनीतिक टिप्पणी थी, श्आपकी राजनीतिक पार्टी को कितने वोट मिले? लोग आपको खारिज करते हैं और आप लोकप्रियता पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं। ... हम पूरे राज्य के लिए एक साथ निर्देश जारी नहीं कर सकते, वह भी किसी राजनीतिक पार्टी की पहल पर।श जेएसपी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 10,000 रुपये हस्तांतरित करके चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कर्ज में डूबे राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 15,600 करोड़ रुपये बांटे।हम जानते हैं कि जेएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, लेकिन यह भी सच है कि जेएसपी को 16 लाख से ज्यादा वोट मिले, जो कुल डाले गए वैध मतों का 3.34 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि जेएसपी राज्य के इतने सारे लोगों की आवाज है, और इसलिए इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की चुनावी विफलता और पब्लिसिटी की कथित तलाश के बारे में कोर्ट की बात में और भी कमियां हैं, जैसे कि संवैधानिक न्यायशास्त्र चुनावी सफलता को कानूनी हैसियत के लिए एक मानदंड के रूप में नहीं मानता, या विफलता को न्याय मांगने के अधिकार की जब्ती के रूप में भी नहीं मानता। ऐतिहासिक रूप से, कई बड़े संवैधानिक मामले उन लोगों द्वारा लाए गए थे जो राजनीतिक रूप से हाशिये पर थे।इसलिए, किसी कानूनी याचिका की स्वीकार्यता तय करते समय याचिकाकर्ता की चुनावी लोकप्रियता को तौलना, संवैधानिक न्यायनिर्णय में एक व्यक्तिपरक और गैर–कानूनी मानक लाने का जोखिम है। न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वह दावों पर फैसला करे, न कि इरादों पर। कोर्ट मामले का गुणदोष सुने बिना इरादे के बारे में कैसे फैसला कर सकता है? राजनीतिक रूप से असफल पार्टियों को भी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे मुद्दे उठाने का अधिकार है, क्योंकि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को नष्ट करते हैं और जिससे सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव मैदान में समान अवसर नहीं मिलता और वे इस गड़बड़ी के शिकार होते हैं।कोर्ट की दूसरी टिप्पणियों के बारे में आलोचकों ने एक और टिप्पणी पर सवाल उठाया है जैसे कि श्किसी को तो उस योजना को ही चुनौती देनी चाहिए थी। वह हमारी प्रार्थना नहीं है। आप बस चुनाव को रद्द घोषित करवाना चाहते हैं,श मुख्य न्यायाधीश ने कह यह भी जोड़ते हुए, श्हम मुफ्त की चीजों के मुद्दे पर विचार करेंगे। लेकिन हमें नेक इरादे भी देखने होंगे... हम किसी ऐसी पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते जो अभी–अभी चुनाव हारी है। जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे।य आखिरी टिप्पणी को पहले लेते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से यह कहना कि जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे, यह सिर्फ कोर्ट की कल्पना है, और यह एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की तरह है, न कि कोई ठोस कानूनी विचार। कोर्ट को ऐसी अटकलबाजी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह किसी के कुछ गलत करने से पहले ही उसे नीचा दिखाना है। एक राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र में एक स्टेक होल्डर होती है, और शायद मुख्य न्यायाधीश का यह कहना सही नहीं हो सकता कि श्हम उस पार्टी के कहने पर (फ्री बीज के मुद्दे को) नहीं देख सकते जो अभी–अभी चुनाव हारी है।य कोर्ट ने कहा कि फिर हमें नेक इरादे भी देखने होंगे। यह समझना मुश्किल है कि चुनाव हारने वाली राजनीतिक पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता के साफ तौर पर उल्लंघन वाले मुद्दे को उठाना नेक इरादा क्यों नहीं है। देश का कोई भी नागरिक नेक इरादे वाला होता है, जब तक यह सिद्ध न हो कि उसके इरादे गलत हैं, और इसलिए उसकी बात सुनी जानी चाहिए, वैसी स्थिति में भी जब वह अपने प्रयासों में पूरी तरह विफल रहे। यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी।

प्रो. एस. प्रणाम सिंह को मिला अधि सदस्यता सम्मान

लखनऊ, (संवाददाता)। राज्य ललित कला अकादमी के 65वें स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन रविवार को अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार और बीएचयू के चित्रकला एवं दृश्यकला विभाग के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर एस. प्रणाम सिंह को अकादमी का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अधि सदस्यता सम्मान दिया गया। उन्हें 51 हजार रुपये की राशि, स्मृति चिह्न, प्रमाणपत्र व अंगवस्त्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर 35वीं वार्षिक राज्यस्तरीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कैसरबाग स्थित अकादमी में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र, राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉ. सुनील विश्वकर्मा और उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र मौजूद रहे। अतिथियों ने अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी– 2025 महाकुंभ, प्रयागराज व अखिल भारतीय मूर्तिकला शिविर–2026, वाराणसी के कैटलॉग का विमोचन किया। समारोह में 35वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के 10 विजेताओं को 25–25 हजार रुपये के पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री राम वनजी सुतार के व्यक्तित्व पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता के 14 विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। प्रो. एस. प्रणाम सिंह ने आजकल के युवा कलाकारों में संभावनाएं तो बहुत हैं लेकिन तकनीक का बहुत ज्यादा प्रयोग उन्हें मौलिकता से दूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अगर अपनी कला को निखारना है और कुछ अलग करना है तो उन्हें दूसरों की नकल करनी छोड़नी होगी। इसके अलावा मोबाइल, इंटरनेट के जरिये कला को विकसित करने का युवाओं का प्रयास उनकी नैसर्गिक प्रतिभा के विकास में बाधक बन रहा है। प्रो. प्रणाम ने कहा कि जब युवा आसपास के सामाजिक परिदृश्य और प्रकृति से सीखकर कुछ रचता है तो वह उसकी मौलिक कृति होती है। आजकल के युवाओं में धैर्य की भी कमी है जिसकी वजह से वे तकनीक के बलबूते जल्द से जल्द बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं। अधि सदस्यता सम्मान मिलने पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान बताता है कि वाकई मैंने कुछ काम किया है। बोले– मणिपुर में मेरा जन्म हुआ और पश्चिम बंगाल से शिक्षा प्राप्त की लेकिन पिछले 40 वर्षों से वाराणसी ही मेरी कर्मभूमि है। उन्होंने कहा कि बीएचयू जॉइन करने के बाद ही मेरे काम को पहचान मिली। सेवानिवृत्ति के बाद भी अस्सी घाट के पास ही मैं विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा हूं।

बीयर के ठेके के पास मिला युवक का शव, मां बोली– हत्या की गईय पुलिस को हादसे का अंदेशा

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी के अमेठी में सोमवार को बीयर के ठेके के पास एक युवक का शव मिला। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची मां ने हत्या करने की बात कही। वहीं, भाई जंगली जानवर के काटने से मौत होने की बात कही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मामले की जांच की जा रही है।

घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के शीतलागंज बाजार की है। यहां विकास वर्मा (35) का शव मिला। वह नोहरी का पुरवा पुन्नपुर का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक के चेहरे पर चोटों के निशान थे। आसपास सामान बिखरा पड़ा था। प्रथम दृष्टया किसी जंगली जानवर के हमला करने की आशंका जताई जा रही है। इससे लोगों के बीच भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक शराब पीने का आदी था। आशंका है कि रात में नशे की हालत में असंतुलित होकर गिरने से उसकी मौत हुई हो। अंधेरे में पड़े रहने के दौरान किसी जंगली जानवर द्वारा चेहरे को नुकसान पहुंचाया गया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का वास्तविक कारण पता चलेगा। मामले की जांच की जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

संघ शताब्दी वर्ष पर भारत वंदना से सजी राष्ट्रभक्ति की संध्या

लखनऊ, (संवाददाता)। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को भारत विकास परिषद अवध प्रांत कृष्णा नगर शाखा व उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुति– भारत वंदना का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में संगीत और राष्ट्रभक्ति का शानदार संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना को सशक्त बनाते हैं। विशिष्ट अतिथि विक्रांत खंडेलवाल ने राष्ट्रगीतों के माध्यम से सामाजिक जागरण के महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जयंत खेत ने की। शाखा अध्यक्ष डॉ. संजीव अवस्थी ने परिषद की सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी। शाखा सचिव शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि यह आयोजन क्षेत्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल की परिकल्पना का परिणाम है। डॉ. सीमा भारद्वाज के संयोजन और केवल कुमार के संगीत निर्देशन में कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी।

विद्यार्थियों को समझाया अध्यात्म का महत्व

लखनऊ, (संवाददाता)। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित श्रीश्री राधारमण बिहारी मंदिर (इस्कॉन) में रविवार को साप्ताहिक "संस्कार शाला" हुई। इसमें निजी स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और मंदिर का भ्रमण किया। मंदिर अध्यक्ष अपरिमेय श्याम प्रभु की पत्नी अचिंत्य रूपिणी के निर्देशन में संचालन हुआ। विद्यार्थियों ने हरिनाम संकीर्तन, तुलसी आरती प्रस्तुत की। अचिंत्य ने बच्चों को नैतिक मूल्यों, सदाचार एवं आध्यात्मिक का महत्व समझाया। अच्छे संस्कार से ही अच्छा व्यक्ति बना जा सकता है। हमेशा अपने माता–पिता और गुरुओं का कहना मानना चाहिए। मदद सिर्फ धन से ही नहीं किया जा सकता। समापन पर प्रसाद वितरित किया गया।

एक्यूप्रेशर थेरेपी का महत्व समझाया

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनर स्थित हिंदी मीडिया सेंटर में लोक जीवन फाउंडेशन की ओर से आयोजित दो दिवसीय "आरोग्य पाकशाला" रविवार को संपन्न हुई। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. वंदना वर्मा ने बताया कि एक्यूप्रेशर, जिसे एक्यूपंक्चर का एक गैर–भेदक रूप माना जाता है। यह प्राचीन उपचार पद्धति शरीर में विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालने पर आधारित है। इससे ऊर्जा प्रवाह को संतुलित किया जा सकता है और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाया जा सकता है। उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक, डॉ. डीके वर्मा ने हर्बल एवं औषधीय पौधों का महत्व समझाया। कृषि विज्ञान केंद्र, कटिया (सीतापुर) के अध्यक्ष डॉ. दया श्रीवास्तव ने जैविक खेती के बारे में बताया। संस्थापक डॉ. राजेश वर्मा ने सभी वैद्याचार्यों को सम्मानित किया। इनमें पीआईबी के पूर्व अपर महानिदेशक अरिमर्दन सिंह, रसोइया रघुराज एवं प्रमोद शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालक प्रिया वर्मा ने किया।

सपा पार्षद बीबीडी थाना परिसर में चार घंटे तक धरने पर बैठीं

लखनऊ, (संवाददाता)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदी राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने से नाराज सपा पार्षद ममता रावत ने रविवार को बीबीडी थाना परिसर में समर्थकों के साथ करीब चार घंटे जमकर धरना–प्रदर्शन किया। पुलिस पर सरकार में शामिल पार्टी के विधायक पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप भी लगाया। फोन पर बीकेटी के भाजपा विधायक योगेश शुक्ला से भी उनकी तीखी झड़प हुई। विधायक बेदी राम पर एफआईआर तो दर्ज नहीं हो हुई, मगर इस मामले में नया मोड़ आया है। अब नगर निगम के लेखपाल ने सपा पार्षद ममता रावत के समर्थकों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। खरगापुर मल्हौर वार्ड की सपा पार्षद ममता रावत ने बताया कि गंगोत्री विहार फेज–टू कॉलोनी में शुक्रवार को नगर निगम की टीम कच्चा नाला खोदने के आई थी, तभी सुभासपा विधायक बेदीराम व उनके लोगों ने नगर निगम की टीम का विरोध किया था। उनको भी अपशब्द कहे व धमकी दी थी। इसका वीडियो वायरल होने पर वह रविवार सुबह करीब 11 बजे विधायक के खिलाफ बीबीडी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचीं, मगर कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन करने के लिए विवश हुईं। बीबीडी इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। दूसरे पक्ष से बात और मामले की जांच व घटनास्थल के निरीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद पार्षद ने शाम को धरना समाप्त कर दिया। इस मामले में नगर निगम के लेखपाल सुभाष कौशल ने पार्षद पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने उसके साथ मारपीट कराई। इस मामले में लेखपाल ने पार्षद पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर रविवार को पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में लेखपाल सुभाष कौशल ने लिखा है कि सात फरवरी को वह बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के बुलाने पर नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचे थे। उसी दौरान भरवारा–मल्हौर वार्ड की पार्षद ममता रावत अपने प्रतिनिधि विजय यादव व अन्य समर्थकों के पहुंची थीं। ममता इस बात पर हंगामा करने लगीं कि उक्त नाले पर अतिक्रमण की शिकायत के मामले में उनका नाम क्यों लिया गया। इसी दौरान प्रायोजित ढंग से पार्षद ममता रावत के उकसाने पर उनके प्रतिनिधि विजय यादव, सचिन यादव व 10 से 12 अन्य समर्थकों ने जबरन उसकी (लेखपाल) कार का गेट खोलकर कॉलर पकड़ कर गाली देते हुए बाहर निकाला और मारपीट करने का प्रयास किया। कार की सीट पर रखी सरकारी पत्रावली छीन ली गई। विजय यादव व उनके अन्य सहयोगियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पास में उपस्थित नायब तहसीलदार व एसटीपी चौकी की पुलिस ने तुरंत किसी तरह से बीच बचाव करके बचाकर उन्हें निकाला।

जनसंख्या के आधार पर लोधी समाज को मिले भागीदारी

लखनऊ, (संवाददाता)। हजरतगंज स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में रविवार को अखिल भारतीय लोधा, लोधी, लोध महासभा की ओर से स्वामी ब्रम्हानंद शैक्षणिक उन्नयन एवं सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी हुई। इसमें अवंती चेतना पत्रिका का विमोचन हुआ। मुख्यअतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि देश–प्रदेश में लोधी की जनसंख्या अधिक है लेकिन संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं है। जनसंख्या के आधार पर राजनीति और सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। बीएल वर्मा ने सामाजिक ढांचे को मजबूत करने व शिक्षा को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि जो समाज शिक्षित एवं संगठित नहीं रहता उस समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षित बनें और संगठित होकर रहें। महासभा के प्रदेश महामंत्री विजय लोधी ने कहा कि साल 2011 की जनगणना में लोधी समाज की आबादी नौ प्रतिशत के करीब रही और इसकी संख्या में इजाफा भी हुआ। लेकिन, संख्या के आधार पर सरकार और राजनीति क्षेत्र में भागीदारी न के बराबर है। हमारी मांग है कि सरकार रोजगार, नौकरी और अन्य क्षेत्रा में बराबर की भागीदारी दें। विधायक टी राजा ने कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया नहीं गया होता तो श्री राम मन्दिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। लोधी समाज की संख्या को देखते हुए किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा संगठन एवं सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है। हमारी मांग है हर क्षेत्र इसकी भागीदारी बढ़े। कार्यक्रम में विधायक विपिन कुमार वर्मा, डीसी वर्मा,अनीता राजपूत व अन्य शामिल हुए।

संक्षिप्त खबरें

जनभवन में प्रदर्शनी के तीसरे दिन उमड़े दर्शक

लखनऊ, (संवाददाता)। जनभवन में लगी 57वीं प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के तीसरे दिन रविवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान ऐसा लगा मानो जनभवन में जन सैलाब उमड़ आया हो। तीसरे दिन यहां डेढ़ लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। प्रदर्शनी का समापन सोमवार को दोपहर तीन बजे होगा और राज्यपाल विभिन्न वर्गों की प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित कर उन्हें पुरस्कृत करेंगी। दर्शक जनभवन स्थित पंचतंत्र वाटिका, नवग्रह, राशि, नक्षत्र वाटिका, मियावकी वन सहित विभिन्न कक्षों का भ्रमण कर इसके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रदर्शनी में विभागीय विशेषज्ञों और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने पाली हाउस में सब्जी उत्पादन, शहद उत्पादन, हाइड्रोपोनिक्स, मशरूम उत्पादन, छत एवं गमलों में सब्जी उत्पादन के साथ ही हाईटेक नर्सरी के माध्यम से उन्नत कृषि तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। बागवानी फसलों से संबंधित साहित्य का निशुल्क वितरण किया गया। प्रदेश के विभिन्न कारागारों की ओर से उत्पादित गुणवत्तापूर्ण शाकभाजियों के साथ गमलों में सुसज्जित अलग–अलग रंगों के मौसमी फूल पेंजी, पिटूनिया, सिनरेरिया, पालीएन्थस, रोडैन्थी, स्वीट विलियम, स्वीट एलाइजम, स्टाक, स्टेटिस, फ्लाक्स, वाल फ्लावर, कार्न फ्लावर, एस्टर, गेंदा, बोगनवेलिया, गुलाब एवं डहेलिया भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैक्टस, सकुलेन्ट्स, फलदार पौधे, शोभाकार पौधे एवं कलात्मक बोन्साई भी आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदर्शनी में प्राकृतिक फूलों से निर्मित मनोहारी आकृतियां आगंतुकों को लुभा रही हैं। इस दौरान एरा विश्वविद्यालय की ओर से सारस पक्षी के जोड़े की आकृति लोगों को खूब भा रही है। इस आकृति को सब्जियों और खूबसूरत फूलों से तैयार किया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर की गई सजावट भी चर्चा का विषय है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अलावा यूपी मेट्रो ने भी फूलों से निर्मित भव्य एवं कलात्मक आकृतियों को प्रदर्शित किया है।

मोटे अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक : राजेश्वर सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रभु रघुवीर सेवा संस्थान की ओर से किसान, गोपालक, चिकित्सक और जवान सम्मान समारोह का आयोजन बख्शी का तालाब क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव में लोकनिर्माण विभाग के विश्रामगृह में किया गया। इस दौरान कुल 80 लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही 250 बच्चों को शैक्षिक सामग्री भी बांटी गई। समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने यहां आयोजित गोष्ठी में कहा कि हमें मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने 20–20 किसान, गोपालक, चिकित्सक और जवानों को सम्मानित करने के बाद उन्हें बधाई दी। आयोजक शुभम सिंह ने बताया कि इस अवसर पर विधायक योगेश शुक्ला, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सदस्य गो सेवा आयोग राजेश कुमार सेंगर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से सत्येंद्र कुमार, अंतरराष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह, एसएस ग्रुप के प्रवीण सिंह, नेशनल शूटर व उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन लखनऊ के सचिव गिरिजा है।

रायबरेली के लिए काला रविवार, अलग-अलग हादसों में आठ मौतें एक्सप्रेसवे पर कार ने चार को कुचला

लखनऊ, (संवाददाता)। रायबरेली के लिए आठ फरवरी काला रविवार बनकर आया। रविवार को हुए अलग–अलग सड़क हादसों में आठ लोगों की मौत हो गई।

देर रात बरात से घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बांदा–बहराइच राजमार्ग पर शोभवापुर गांव के पास रविवार को ई रिक्शा को बचाने में दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने–सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार देर शाम चूली गांव के पास कार ने पैदल जा रहीं सात युवतियों व किशोरियों को रौंद दिया। इसमें चार युवतियों की मौत हो गई। तीन की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस के अनुसार सभी पैदल ही एक्सप्रेसवे होते हुए गांव जा रही थीं। इसी दौरान हादसे की शिकार हो गईं। पुलिस के अनुसार जगतपुर क्षेत्र के कोडर निवासी शालिनी (20), बहन साधना (15), भदोखर क्षेत्र के अलीगंज निवासी हिमांशी (22), रश्मि (15), आसमां (18) समेत सात युवतियां व किशोरियां रविवार को चूली गांव में आयोजित भंडारे में शामिल होने गई थीं। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे से पैदल ही घर के लिए निकलीं। शाम सात बजे एक्सप्रेसवे से गुजर रही कार ने सभी युवतियां को रौंद दिया। हादसे की जानकारी पर आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को सीएचसी जगतपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शालिनी, हिमांशी को मृत्यु घोषित कर दिया। अन्य को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में आसमां व रश्मि ने भी दम तोड़ दिया। सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। कार को कब्जे में लिया गया है। बरात से घर लौट रहे तीन दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार देकर डॉ. सौरभ सिंह ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शिवगढ़ क्षेत्र के जगन्नाथ पुर मजरे सूरजपुर के रहने वाले शंकर (28) शिवगढ़ के बैंती निवासी अपने दोस्त पप्पू (30) व रोहित (30) के साथ बाइक से बछरावां से एक बरात में शामिल होने के बाद देर रात करीब 11.30 बजे बाइक से घर लौट रहे थे। स्टेट हाइवे बांदा बहराइच मार्ग स्थित शिवगढ़ बछरावा मार्ग पर गुड़िया गढ़ी के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे शंकर की मौके पर मौत हो गई वहीं रोहित और पप्पू भी कुचल गए। दोनों ने किसी तरह पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया स पुलिस के मुताबिक बाइक चालक ने हेलमेट नहीं लगाया था। बांदा– बहराइच राजमार्ग पर शोभवापुर गांव के पास रविवार को ई रिक्शा को बचाने में दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने–सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सरेनी थाना क्षेत्र के रावतपुर कला गांव निवासी तेज बहादुर (28) पुत्र छेदीलाल बाइक से चचेरे भाई रामप्रसाद (32) और मंगाखेड़ा मजरे सेमरपहा गांव निवासी मामा धुन्नर (30) के साथ लालगंज से सरेनी जा रहे थे। बाइक तेज बहादुर चला रहे थे। खीरों थाना क्षेत्र के पाहो गांव निवासी महेंद्र सिंह (55) पुत्र रामराज सिंह गेगासों गंगाघाट से अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे। शाम 4:45 बजे शोभवापुर गांव के पास एक ई रिक्शा को बचाने में दोनों बाइकों की आमने–सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएचसी लालगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने महेंद्र सिंह और तेज बहादुर को मृत घोषित कर दिया। राम प्रसाद और धुन्नर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे की खबर से परिजनों में रोना पीटना मच गया। लालगंज कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की जांच कराई जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। पिलखा गांव के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार ई रिक्शा ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद भाग रहे ई रिक्शा चालक को पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। भानमती (55) पत्नी जगतपाल आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना में मजदूरी करती थीं। सुबह घर से पैदल काम पर जा रही थीं। गांव के पास पीछे से आए ई रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला सड़क पर गिर पड़ी। राहगीरों की मदद से परिजन उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई है। महिला की मौत की जानकारी होने पर घरवालों में चीख पुकार मच गई। पति जगतपाल, बेटे राहुल व सुनील और बेटी लक्ष्मी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

जहां था नाला वहां की जमीन प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच डाली

लखनऊ, (संवाददाता)। भरवारा मल्हौर वार्ड में आने वाली गंगोत्री विहार कॉलोनी में नाला खोदने के मुद्दे पर हुए विवाद को लेकर अमर उजाला ने रविवार को मौके पर जाकर पड़ताल की। स्थानीय लोगों के अनुसार नाले का रास्ता बदला जा रहा है। जहां से नाला बहना चाहिए वह जमीन प्रॉपर्टी डीलरों ने बेच डाली है। अब प्रॉपर्टी डीलरों की बसाई कॉलोनी की जल निकासी के लिए चक मार्ग जो कि मुख्य रास्ता है, उस पर नगर निगम नाला बनाने का प्रयास कर रहा है। गांव के लोग इस बदलाव के विरोध में हैं। शुक्रवार शाम नगर निगम के लेखपाल सुभाष कौशल का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आरोप लगाया गया है कि लेखपाल सुभाष सरकारी जमीन पर कब्जा करके बने बेदी लॉन से कब्जा हटवाने के लिए पहुंचे थे। मौके पर लॉन के मालिक गाजीपुर के जखनिया के सुभासपा विधायक बेदी राम ने लेखपाल को फोन पर धमकाया और गालियां दीं। जब लेखपाल ने बताया कि वह पार्षद ममता रावत की शिकायत पर आए हैं तो विधायक ने पार्षद के लिए भी अपशब्द कहे। अमर उजाला वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस विवाद के बाद शनिवार को भाजपा विधायक योगेश शुक्ला नगर निगम की टीम के साथ मौके पर गए। उन्होंने कहा था कि अवैध कब्जा हटवाया जाएगा। दौरान गांव के लोगों ने बताया कि यह विवाद नगर निगम और एलडीए की वजह से है। नगर निगम जहां पर नाला बनाने का प्रयास कर रहा

है वह चक मार्ग की जमीन है। दूसरी ओर सरकारी अभिलेखों में जहां नाला है वह जमीन प्रापर्टी डीलरों ने बेच डाली है। उसको खाली कराने के बजाय नगर निगम चकमार्ग की जमीन पर ही नाला बनाने की तैयारी में है। अगर रास्ते की जमीन पर नाला बना तो लोग कहां से आएंगे–जाएंगे। वहीं, विधायक बेदी राम कह रहे हैं कि उनके लॉन का निर्माण सही है। हालांकि, नगर निगम का दावा है कि विधायक के मैरिज लॉन में भी चकमार्ग की जमीन है। गांव के निवासी दिनेश सिंह, महेश, अरविंद, सर्वेश पाल, अरुण कुमार यादव ने बताया कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए भरवारा के खसरा संख्या–1041 में नाला खोदवाना चाहते हैं जबकि यह जमीन राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। नाले के लिए अभिलेखों में भरवारा व भैंसोरो के कई खसरा नंबरों की जमीन दर्ज है। नक्शे पर नाला एसटीपी रोड में जाकर मिलता है। नक्शे के आधार पर ही नाला बनना चाहिए, मगर नगर निगम मनमानी कर रहा है।

बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का असंतुलित उपयोग खतरनाक हो सकता है : प्रो अजय प्रताप

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,10 फरवरी । यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संकाय भवन में साइबर क्लब के तत्वावधान में मंगलवार को सेफर इंटरनेट डे 2026 के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम स्मार्ट टेक, सुरक्षित निर्णय कृ एआई का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग रही। कार्यक्रम में आधुनिक डिजिटल युग में बढ़ते ऑनलाइन जोखिमों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के सुरक्षित एवं जिम्मेदार प्रयोग पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम में वैलनेस सेंटर के समन्वयक प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का असंतुलित उपयोग खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर इंटरनेट ने जीवन के अनेक आयामों को सहज और सुविधाजनक बनाया है, वहीं एआई ने कई नई चुनौतियों और समस्याओं को भी जन्म दिया है। ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार ने कहा कि एआई का प्रयोग जीवन में बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज नई और पुरानी दोनों पीढ़ियाँ एआई से प्रभावित हो रही हैं, ऐसे में सजगता और जिम्मेदार व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंजीनियरिंग संस्थान के डॉ. द्विवेंदु मिश्र ने सेफर इंटरनेट डे की थीम पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि इंटरनेट पर लगभग 90 प्रतिशत सुरक्षा हमारी "गुड प्रैक्टिसेज" पर निर्भर करती है, इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो हम बहुत–सा डेटा साइबर स्पेस में छोड़ते हैं, ऐसे में सुरक्षा के उपायों से परिचित होना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि आम व्यक्ति का डिजिटल व्यवहार निरंतर साइबर स्पेस में विश्लेषित किया जा रहा है और उसी आधार पर उसे लक्षित किया जाता है। डॉ. मिश्र ने जोर देते हुए कहा कि एआई और इंटरनेट का उपयोग रचनात्मक, शैक्षणिक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, ताकि तकनीक मानव जीवन को बेहतर बना सके। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा एआई सुरक्षा एवं डीपफेक जागरूकता, वॉइस क्लोनिंग एवं फिशिंग स्कैम, पासवर्ड व मोबाइल सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव तथा जिम्मेदार एआई प्रथाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम का विषय–प्रवर्तन एवं संचालन साइबर क्लब के नोडल अधिकारी डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर ने किया।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा एक की मौत कई घायल

सुलतानपुर। लखनऊ से सवारी लेकर आजमगढ़ जा रही एक प्राइवेट बस और पीछे से आ रही डीसीएम आईसर के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 140.700 के पास उस समय हुई,जब बस चालक ने सवारी बैठाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे से आ रही डीसीएम बस में जा भिड़ी और टक्कर के बाद डीसीएम सड़क पर पलट गई।हादसे में डीसीएम में सवार मोहम्मद अनीस (30) निवासी पुर बादली थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डीसीएम चालक इम्तियाज अहमद, मोहम्मद इसराइल तथा कंडक्टर मुदस्सिर गंभीर रूप से घायल हो गए।बस में सवार यात्रियों शिवांगी मौर्य, रशीदा, साजिदा और लुकमान समेत अन्य को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को तत्काल सरकारी एंबुलेंस से दोस्तपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया,जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है।सूचना मिलते ही सुरक्षा अधिकारी व पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई।हादसे के बाद बस का चालक व कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारू कराया गया।

संक्षिप्त खबरें

अयोध्या के रहने वाले सरवन कुमार ने यूजीसी नेट–पीएचडी परीक्षा किया पास, दी शुभकामनाएं

अयोध्या(Dku live ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार। अयोध्या के रहने वाले सरवन कुमार ने यूजीसी द्वारा आयोजित नेट–पीएचडी परीक्षा में लॉ विषय से उन्होंने अपने पहले प्रयास में कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन के बल पर यह उपलब्धि हासिल कीAjou ने साकेत विद्यालय से 2023 में LLB स्नातक किया हैं और 2025 में Monad University Hapur से LLM किया है अपनी सफलता का श्रेय अपने ऑनलाइन टेस्ट तथा गुरुजनों और घर परिवार वालों के मार्गदर्शन को दिया। सरवन ने कहा कि उनका लक्ष्य आगे चलकर प्रोफेसर बनकर शिक्षा के माध्यम से देश की सेवा करना है। इस सफलता पर गुरुजनों और परिवार जनों और मित्रों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं।

26 करोड़ से बहरैची में बनेगा दूसरा सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय

भदोही, (संवाददाता)। भदोही तहसील के बहरैची में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 26 करोड़ का स्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिया है। जिले के दूसरे सीएम मॉडल विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें करीब दो हजार बच्चों का नामांकन होगा। जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। कॉन्वेंट विद्यालयों जैसी सुविधा के लिए जिले की तीन तहसीलों में एक–एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनना है। औराई ब्लॉक के गिर्दबड़गांव में स्कूल का निर्माण कार्य शुरू चल रहा है। भदोही के बहरैची में जमीन चिह्नित की गई थी। अब शासन से स्वीकृति मिलने पर स्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है। विद्यालयों में कक्षा एक से 12 तक की कक्षाएं चलाई जाएंगी। ज्ञानपुर के घरांव में जमीन का चयन किया जा चुका है। पांच से छह एकड़ भूमि में विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। शिवम पांडेय, बीएसए ने बताया कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय तीनों तहसीलों में बनना है। औराई के गिर्दबड़गांव में काम चल रहा है। बहरैची में अप्रैल से काम शुरू होने की संभावना है। घरांव में आगामी वर्ष में स्वीकृति मिलने पर निर्माण होगा। बहरैची में बनने वाले विद्यालय पर 26 करोड़ रुपये खर्च होंगे।सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय में स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस व कंप्यूटर लैब, हॉल, खेलकूद का मैदान, मॉड्यूलर किचन, डाइनिंग हॉल के साथ, सीसीटीवी कैमरे, सोलर पैनल आदि आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। औराई के गिर्दबड़गांव में निर्माणाधीन मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण करीब–करीब 50 फीसदी तक पूर्ण हो गया है। शासन की प्राथमिकता में शामिल होने के कारण नोडल अफसर से लेकर डीएम शैलेष कुमार हर महीने उक्त विद्यालय का निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट लेते हैं।

4 किमी की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलीं

भदोही, (संवाददाता)। जिले के मौसम में बदलाव जारी है। रविवार को धूप खिली। इससे अधिकतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई। अधिकतम पारा 25.6 डिग्री रहा। शाम होते ही 14 किमी की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलीं। इससे लोगों ठंड का अहसास हुआ। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि सोमवार से तापमान में और वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि सोमवार से तापमान में वृद्धि के आसार है। तेज पछुआ हवाओं के कारण कोहरे का दौर अब धीरे–धीरे सिमटने लगा है। आगामी दो से तीन दिनों के अंदर तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिन का तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। बेजवां के कृषि विशेषज्ञ आरपी चौधरी ने बताया कि सुबह शाम ठंड और दोपहर में धूप फसलों के लिए फायदेमंद है। खासकर यह मौसम गेंहू की फसल के लिए उत्तम है। आलू की खुदाई किसान शुरू दें।

वाराणसी और प्रयागराज के लिए भदोही से बस सेवा नहीं

भदोही, (संवाददाता)। भदोही नगर में राजकीय बस स्टैंड का निर्माण होने के बाद भी वाराणसी–प्रयागराज आने–जाने के लिए बस सेवा की शुरूआत नहीं हुई है। इससे लोग पूरी तरह से रेलवे पर आश्रित है। काफी संख्या में लोगों का प्रतिदिन वाराणसी और प्रयागराज जाना होता है। प्रयागराज के लिए लोगों को प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता है जबकि वाराणसी जाने वालों को केवल ट्रेन का ही सहारा है। दुर्गागंज, सुरियावां, मोढ़, भदोही, चौरी से हजारों व्यापारी, छात्र और कर्मचारी वाराणसी जाते हैं। यात्रियों का कहना है कि जीप में आठ के बजाय 15 यात्री सवार हो जात हैं। वहीं निजी बस से वाराणसी पहुंचने में दो से तीन घंटे का समय लग जाता है। यात्री रामराज यादव ददा ने कहा कि भदोही के जमुनीपुर में कई वर्ष से राजकीय बस स्टैंड बनकर तैयार है लेकिन बसें नहीं चलाई जा रही हैं। बताया कि प्रयागराज में माघ मेला अथवा विशेष आयोजन होने पर बसें संचालित की जाती हैं फिर रोक दी जाती हैं। इस बारे में परिवहन निगम के के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि भदोही से मिर्जापुर और जौनपुर के लिए बसें जाती हैं। प्रयागराज और काशी के लिए औराई से बस चलती हैं।

जिलाधिकारी ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने एनआईसी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष मतदाता पुनरीक्षण के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में अनमैप्ड मतदाताओं को नोटिस तामील कराने और सुनवाई सहित अन्य बिंदुओं पर विधानसभावार ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान, शत–प्रतिशत नोटिस तामील करने और साक्ष्य मिलान हेतु सुनवाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एईआरओ को प्रोत्साहित व सम्मानित किया गया। वहीं, खराब प्रगति वाले एईआरओ को चेतावनी देते हुए अगले एक–दो दिन में सुधार करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानंद झा, मुख्य राजस्व अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, समस्त ईआरओ एवं एईआरओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उप निदेशक कृषि, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग ने भाग लिया।

कोडीन कफ सिरप के आरोपी भोला जायसवाल एनडीपीएस की कोर्ट में पेश,18 फरवरी सुनवाई की अगली तारीख

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में कोडीन युक्त कफ सिरप प्रकरण में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की मंगलवार को दीवानी न्यायालय स्थित एडीजे द्वितीय की अदालत में पेशी हुई। इस दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भोला प्रसाद जायसवाल मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता हैं, जिन पर फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से जौनपुर जिले की 16 फर्मों के जरिए लगभग 42.5 करोड़ रुपये के संदिग्ध कारोबार का आरोप है। औषधि विभाग की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि उक्त फर्मों के नाम पर बड़े पैमाने पर बिलिंग की गई, जबकि वास्तविक लेन–देन संदिग्ध पाया गया। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस के साथ–साथ एसआईटी भी गहन जांच में जुटी हुई है। इस मामले में जानकारी देते हुए सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को आरोपी भोला जायसवाल को एडीजे द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाए जाने के संबंध में पेश किया गया। न्यायालय में रिमांड की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके तहत आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(ग), 27(ग) एवं 29 की बढ़ोत्तरी की गई है।उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि नियत की गई है। अदालत में पेशी के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा और न्यायालय परिसर की सघन निगरानी की गई। पुलिस और जांच एजेंसियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

ई–रिक्शा चालकों की रोजी–रोटी पर हमला, कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने लगाया भेदभाव का आरोप

अयोध्या (Dku liv ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार अयोध्या। शहर के एक होटल में श्री अयोध्या जी ई–रिक्शा कल्याण समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने ई–रिक्शा चालकों के हितों को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ई–रिक्शा चालकों का मामला सीधा रोजी–रोटी से जुड़ा है। अयोध्या का विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहां गरीबों के रोजगार पर ही संकट खड़ा किया जा रहा है।शरद शुक्ला ने कहा कि लोगों ने कर्ज लेकर ई–रिक्शा खरीदे हैं, लेकिन धार्मिक नगरी के नाम पर इन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है। प्रशासन की नजर केवल गरीब ई–रिक्शा चालकों पर है, जबकि गोल्फ कार्ट को अंदर चलाने की पूरी अनुमति दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गोल्फ कार्ट चल सकती हैं तो ई–रिक्शा क्यों नहीं।उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने एआरटीओ से आरटीआई के जरिए पूछा कि कितने चालान काटे गए हैं लेकिन कार्रवाई शून्य थी।ई रिक्शा पर रोक लगाई गई और पांच फरवरी से यह योजना लागू कर दी गई है, जिसके तहत अयोध्या धाम में ई–रिक्शा नहीं चलने दी जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि जाम का ठीकरा ई–रिक्शा चालकों पर फोड़ा जा रहा है, जबकि बड़े वाहन और गोल्फ कार्ट से भी जाम लगता है।शरद शुक्ला ने कहा कि विकास प्राधिकरण द्वारा आस्था और राम रथ के नाम से 165 गोल्फ कार्ट चलाई जा रही हैं। 22 जनवरी को इस संबंध में पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। न तो ई–रिक्शा के लिए स्टैंड बनाए गए हैं और न ही कोई वैकल्पिक समाधान दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है।उन्होंने मांग की कि ई–रिक्शा के लिए चार से पांच मीटर के अंतराल पर स्टैंड बनाए जाएं, सामान्य दिनों में यात्रियों के लिए एक पथ खाली रखा जाए और सीमित संख्या में ई–रिक्शा चलने दी जाएं। साथ ही आधार कार्ड के माध्यम से हर चालक को एक ई–रिक्शा पास जारी करने की भी मांग की।प्रेसवार्ता में ई–रिक्शा चालकों ने भी अपनी पीड़ा रखी। चालक खुश्बू साहू ने कहा कि अगर ई–रिक्शा नहीं चलेगी तो बच्चों का पालन–पोषण कैसे होगा। चालकों ने आरोप लगाया कि अवैध रूप से चल रही गोल्फ कार्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि सारी कार्रवाई गरीब ई–रिक्शा चालकों के खिलाफ की जा रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अयोध्या के गरीबों के साथ अन्याय कर रही है और मेहनत से काम करने वालों को खत्म करने की मंशा साफ नजर आ रही है।शाहिद खान उर्फ सोनू प्रबंधक
इंद्रपाल साहू उप्र प्रबंधक
धनेश सोनी अध्यक्ष
विशाल गुप्ता कोषअध्यक्ष
रोहित साहू महासचिव
मोहम्मद सईद उर्फ सोनू सचिव
नीरज सोनकर उपाध्यक्ष
उषा साहू महामंत्री
आफताब अली मुख्य संयोजक
विजय गुप्ता नगर उपाध्यक्ष
गणेश जयसवाल सदस्य
अब्बास सदस्य

अफसरों की खामोशी में घूट रहा कलेक्ट्रेट परिसर कचहरी बनी जाम की प्रयोगशाला

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिस परिसर से जिले की कानून–व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक फैसले निकलते हैं, वही कलेक्ट्रेटदृकचहरीदृविकास भवनदृरजिस्ट्री कार्यालय आज अव्यवस्था, अराजकता और ट्रैफिक जाम का स्थायी अड्डा बन चुका है। हालात यह हैं कि पूरा कैंपस दिनभर चार पहिया वाहनों से भरा रहता है लेकिन जिम्मेदारी संभालने वाले अफसरों को यह अव्यवस्था शायद दिखाई नहीं देती। सुबह से शाम तक सैकड़ों फोर व्हीलर बिना रोक–टोक परिसर में घुस जाते हैं। न कोई तय पार्किंग, न प्रवेश–निकास का अनुशासन। नतीजा यह कि कचहरी के भीतर ही जाम लग जाता है और पैदल चलना तक दूभर हो जाता है। बुजुर्ग, महिलाएं, फरियादी और कर्मचारी घंटों जूझते रहते हैं जबकि 'व्यवस्था के मालिक' अपनी गाड़ियों से सीधे दफ्तरों तक पहुंच जाते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कचहरी परिसर से जुड़ी सड़कों पर भी अक्सर लंबा जाम लग जाता है जिससे पूरा शहर प्रभावित होता है। कई बार आपात सेवाओं के वाहन तक जाम में फंस जाते हैं लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था सुधारने की दिशा में कोई ठोस पहल होती नजर नहीं आती। परिसर में स्थित पत्रकार भवन तक पहुंचना भी अब किसी परीक्षा से कम नहीं है। पत्रकारों का कहना है कि कई बार घंटों जाम में फंसना पड़ता है और जरूरत पड़ने पर भी वाहन बाहर नहीं निकल पाते। सवाल यह उठता है कि जब हर दिन अफसर इसी जाम से गुजरते हैं तो फिर यह समस्या उन्हें 'क्यों नहीं दिखती'? फरियादियों में आक्रोश है कि नियम–कानून सिर्फ आम आदमी के लिए बने हैं। रसूखदारों की गाड़ियां परिसर में बेधड़क दौड़ती हैं और आम नागरिक जाम में फंसा रह जाता है। लगता है कि अव्यवस्था को ही व्यवस्था मान लिया गया है। अब जनता की मांग है कि कचहरी परिसर को तत्काल नो–व्हीकल जोन घोषित किया जाय, बाहरी पार्किंग की प्रभावी व्यवस्था हो और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए सख्ती बरती जाए। वरना यह जाम किसी दिन बड़े हादसे की वजह बन सकता है जिसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जायेगा।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित करना है कि मेरा NO-135021-HAV/GD प्रदीप कुमार सिंह पत्नी सुमन देवी जन्मतिथि 01–01–1983 पुत्र युवराज सिंह की जन्मतिथि 04–04–2007 सही है। जबकि डॉक्युमेंट में दर्ज 05–04–2007 जन्म तिथि गलत है। जिसे अग्रेजी में भी नीचे प्रकाशित किया गया है
- No 135021-HAV/GD Pradip Kumar Singh His Wife Suman Devi Date of Birth 01-01-1983 is correct for Document corretion for Son Yuvraj Singh his Date of Birth 04-04-2007 is correct Date 05-04-2007 worng-

–प्रदीप कुमार सिंह
मोबाइल नंबर
7896119324

लेखपाल मोतीलाल सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट का आदेश

जिला संवाददाता डॉ अजय तिवारी अयोध्या प्रधान प्रतिनिधि व रोजगार सेवक के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रिपोर्ट लगाने के मामले में लेखपाल मोती लाल सहित राजीव व संजय तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधांशु शेखर उपाध्याय ने जिला अधिकारी द्वारा गठित कमेटी की प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पारित किया है। सीजेएम ने थाना कोतवाली बीकापुर की पुलिस को तीन दिन में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय को सूचित करने का निर्देश भी दिया है। पीड़िता के अधिवक्ता कमलेश कुमार पाण्डेय व राजेन्द्र तिवारी के अनुसार थाना कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के बल्लीपुर निवासिनी संगीता ने जिलाधिकारी अयोध्या को पत्र देकर गांव के ही राजीव व संजय तिवारी द्वारा बंद किए रास्ता को खुलवाए जाने की मांग किया था। मौके पर जांच करने गए लेखपाल मोतीलाल ने स्पॉट मेमो बनाया और रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेज दिया। संगीता ने जब जांच रिपोर्ट के बारे में पता कराया तो उस पर प्रधान प्रतिनिधि मुकुल आनंद व रोजगार सेवक बबलू प्रसाद के हस्ताक्षर बने हुए थे। जबकि लेखपाल की जांच के समय मुकुल व बबलू मौजूद नहीं थे।जब लेखपाल मोतीलाल से संगीता ने इस बारे में पूछा गया तो कहा कि राजीव व संजय तिवारी के कहने पर हमने रिपोर्ट लगाई है जो करना है कर लो। पीड़िता द्वारा पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से लेखपाल द्वारा बनाए गए फर्जी हस्ताक्षर व झूठी रिपोर्ट के बाबत कार्यवाही किए जाने की मांग की गई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।तब अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने एसडीएम बीकापुर से मामले में प्रारंभिक जांच कर आख्या तलब किया लेकिन लेखपाल मोतीलाल के बारे में कोई जांच न करते हुए आधी अधूरी आख्या कोर्ट को भेजी गई।एसडीएम की प्रारंभिक जांच में की गई लापरवाही को पीड़िता के अधिवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने अदालत के समक्ष पेश किया।पीड़िता के अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होने के बाद अदालत ने जिला अधिकारी अयोध्या को जांच करने का आदेश पारित किया साथ ही भविष्य के लिए एसडीएम बीकापुर को न्यायालय के आदेश की जांच सरसरी तौर पर न करने की हिदायत भी दिया। जिला अधिकारी द्वारा एडीएम के नेतृत्व में जांच कराई गई जिसमें लेखपाल मोतीलाल पर प्रधान प्रतिनिधि मुकुल आनंद व रोजगार सेवक बबलू प्रसाद के हस्ताक्षर बनाकर रिपोर्ट लगाए जाने की पुष्टि की गई।अदालत ने पीड़िता के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद थाना कोतवाली बीकापुर की पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पारित किया है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।